नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 124
दि. 02.09.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता के साथ योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करना लक्ष्य: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ख' के अधिकारियों की नियमित भर्ती पूरी होने के बाद नवचयनित 40 अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे अंतराल के बाद हुई इस भर्ती से बोर्ड की कार्यक्षमता मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी।

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ख' के अधिकारियों की नियमित भर्ती पूरी होने के बाद नवचयनित 40 अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लंबे अंतराल के बाद हुई इस भर्ती से बोर्ड की कार्यक्षमता मजबूत होगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को नई गति मिलेगी।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं में ऐसी चयन व्यवस्था को मजबूत करना है, जिसमें पारदर्शिता के साथ योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लागू की गई नई भर्ती प्रक्रिया इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी सीधे प्रदेश के पर्यावरण और लोगों के स्वस्थ जीवन से जुड़ी है। ऐसे में नवचयनित अधिकारी अपनी तकनीकी दक्षता का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ करें।

सीएम ने अधिकारियों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और विभागीय कार्यप्रणाली के साथ मैदानी स्तर की चुनौतियों को समझने के निर्देश दिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में समूह 'ख' के 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, कुल 40 अधिकारियों का चयन किया गया है। चयनित अधिकारियों में 21 विभिन्न आईआईटी से शिक्षित हैं, जबकि अन्य अधिकारियों ने देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है।

चयनित अधिकारियों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। इस भर्ती की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देश और सिद्धांतों के अनुरूप चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। पहले बोर्ड में समूह 'ख' के अधिकारियों की भर्ती मुख्य रूप से केवल साक्षात्कार के आधार पर की जाती थी। पुरानी

विनियमावली, 1995 में संशोधन कर चयन प्रक्रिया को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आधारित द्विस्तरीय व्यवस्था में बदला गया।

नई व्यवस्था में लिखित परीक्षा को 85 प्रतिशत और साक्षात्कार को 15 प्रतिशत अंक का वेटेज दिया गया। इससे चयन में शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता को प्रमुख आधार बनाया गया। संशोधित विनियमावली के बाद 27 फरवरी, 2026 को 26 सहायक पर्यावरण अभियंता और 14 सहायक वैज्ञानिक अधिकारी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया।

27 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न शहरों में एक साथ लिखित परीक्षा आयोजित हुई, जिसका आयोजन आईआईटी कानपुर के माध्यम से कराया गया। लिखित परीक्षा का परिणाम 8 जून को घोषित किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में चार साक्षात्कार पैनल गठित किए गए।

पैनल में विभिन्न आईआईटी और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। 4 जुलाई को साक्षात्कार पूरा हुआ और 8 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इस बार नवचयनित अधिकारियों को सीधे क्षेत्र में तैनाती देने के बजाय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों के लिए एक माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण के तहत एक सप्ताह का कार्यक्रम आईआईएम, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है।

सरकार का मानना है कि तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों की नियमित भर्ती और उन्हें प्रशिक्षण देने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन और मैदानी कार्यों की प्रभावशीलता में सुधार होगा।

हरीश द्विवेदी ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी सियासत पर हुई अहम चर्चा

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर अहम मुलाकात की है. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी की सियासत और संगठनात्मक विषयों पर लंबी चर्चा हुई.

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री और बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अहम मुलाकात की है. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण करने के बाद हरीश द्विवेदी की सीएम योगी के साथ यह पहली आधिकारिक और शिष्टाचार भेंट थी.

यह महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, 5 कालिदास मार्ग पर संपन्न हुई, जहां दोनों दिग्गज नेताओं के बीच सूबे की राजनीति और संगठन से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री से इस खास मुलाकात के बाद हरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी एक तस्वीर भी साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा कि "उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक एवं राजनीतिक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई." पूर्वांचल की राजनीति में हरीश द्विवेदी का एक मजबूत जनाधार माना जाता है, ऐसे में उनकी इस नई जिम्मेदारी और सीएम योगी से मुलाकात को आगामी राजनीतिक रणनीतियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

मुलाकातों के इस दौर की मुख्य बातें

सीएम योगी से आशीर्वाद लेने के बाद हरीश द्विवेदी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी उनके आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पंकज चौधरी से भी मुलाकात कर संगठन की मजबूती को लेकर अपने विचार साझा किए.

संगठन को धार देने की तैयारी

राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाकर जो भरोसा जताया है, उसके बाद उनका पूरा फोकस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को निचले स्तर तक मजबूत करने पर है.

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों अपने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में जुटी हुई है. हरीश द्विवेदी का बस्ती और उसके आसपास के पूर्वांचल बेल्ट में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव है. उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए ही पार्टी आलाकमान ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

पीएम मोदी एसआरसीसी के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल, 5 सितंबर को होगा आयोजन

दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) अपने 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह मना रहा है. 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है, जहां छात्रों और युवाओं के साथ उनका संवाद मुख्य आकर्षण रहेगा.

(जीएनएस)।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी रफ्ठउ के लिए यह साल बेहद खास और ऐतिहासिक है. देश के प्रमुख कॉमर्स कॉलेजों में शुमार SRCC अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है. इस खास उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह में 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे.

SRCC ने बीते एक शताब्दी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. कॉमर्स और अर्थशास्त्र की शिक्षा के साथ-साथ कॉलेज ने देश को अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व देने वाली कई पीढ़ियां तैयार की हैं. शिक्षा, उद्योग, प्रशासन, राजनीति और कॉरपोरेट जगत में रफ्ठउ के पूर्व छात्रों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

पीएम मोदी ने की थी सराहना

करीब चार महीने पहले, 25 अप्रैल को SRCC की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस दौरान प्रधानमंत्री ने कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने को एक बड़ी उपलब्धि बताया था. उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में SRCC के लंबे योगदान और उसकी शैक्षणिक विरासत की सराहना भी की थी. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रफ्ठउ ने लंबे समय से देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. कॉलेज ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए सक्षम और प्रभावशाली नेतृत्व तैयार करने में योगदान दिया है.

यही वजह है कि SRCC आज भी देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है.

शताब्दी वर्ष के इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए रफ्ठउ पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया था. यह कॉलेज की सौ साल की शैक्षणिक यात्रा और उसके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली एक विशेष पहचान के तौर पर देखा जा रहा है.

जीडीएपी पर आर-पार: पीएम मोदी ने की तारीफ तो कांग्रेस ने कसा तंज, खड़गे बोले- लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन की शिकार है अर्थव्यवस्था'

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% GDP ग्रोथ पर सियासत तेज है। पीएम मोदी ने इसे देश की सामूहिक ताकत बताया, जबकि खड़गे ने '3-व' (बेरोजगारी, महंगाई, असमानता) का आरोप लगाकर सरकार को घेरा।

(जीएनएस)।

जीडीपी (GDP) विकास दर के ताजा आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी टकराव तेज हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला बोला और तंज भी कसा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म '' पर एक वीडियो संदेश जारी कर जीडीपी के आंकड़ों पर खुशी जताई थी, और विपक्षी दलों पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीडीपी ग्रोथ के सरकारी जश्न पर कड़ा ऐतराज जताया।

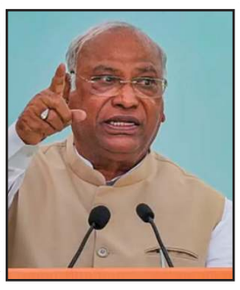

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी सरकार की कहानी 'लाइट्स, कैमरा और इनएक्शन' वाली पीआर (PR) स्टंट बनकर रह गई है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री भले ही जीडीपी आंकड़ों का जश्न मना रहे हों, लेकिन देश के आम आदमी के पास यह सहूलियत नहीं है। आज देश का आम नागरिक '3-U' की मार झेल रहा है और इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने '3-U' की व्याख्या करते हुए सरकार पर तीन बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 'देश अभूतपूर्व बेरोजगारी, असहनीय महंगाई और बेकाबू असमानता से जूझ रहा है।' उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और 40 फीसदी शिक्षित युवा बेरोजगार हैं।

जुलाई 2026 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ' उन्होंने कहा कि 15 से 29 वर्ष की आयु के 6 में से 1 युवा के पास काम नहीं है, जिससे हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरी तरह टूट चुका है।

रसोई के बजट और महंगाई पर सरकार को घेरा

महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए खड़गे ने कहा कि खुदरा महंगाई दर 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। चीनी, प्याज, टमाटर, दाल, खाने का तेल, चावल और दूध जैसी रसोई की हर जरूरी चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं।

पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार किसी तरह अपनी आजीविका चला रहे हैं, जबकि गरीब तबका अब जीवन जीने की उम्मीद छोड़ चुका है।

1 सितंबर से जेब पर सीधा हमला! दूध, सिलेंडर के दाम बढ़े, कार खरीदना भी महंगा, लागू हुए 5 बड़े नियम

सितंबर की शुरूआत आम लोगों के लिए राहत वाली नहीं है। 1 सितंबर 2026 से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। मुंबई में थोक दूध महंगा हुआ है। एलपीजी की ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के लिए सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन का एक पुराना नियम बदला है। वहीं टाटा और हुंडई की कारें भी महंगी हो गई हैं। आइए एक-एक करके समझते हैं कि इन बदलावों का आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।

तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है।

उचित दर विक्रेताओं का लाभांश ₹35 प्रति क्विंटल बढ़ा

बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ-खाद्य मंत्री का जताया आभार, अब ₹125 प्रति क्विंटल मिलेगा लाभांश

(जीएनएस)।

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) के लाभांश में ₹35 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें ₹125 प्रति क्विंटल लाभांश मिलेगा। इस फैसले पर उचित दर विक्रेता कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय का आभार जताया है।

समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र बोस सिंह रावत ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन भेजा। इसमें कहा गया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के सभी उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। लाभांश ₹90 से बढ़ाकर ₹125 प्रति क्विंटल किया गया है, जो विक्रेताओं के हित में एक अहम कदम है।

समिति ने बताया कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक अनाज पहुंचाने का काम करते हैं। लाभांश बढ़ने से उनके आर्थिक हित मजबूत होंगे। साथ ही सरकार के प्रति उनकी जिम्मेदारी और सेवा भावना को भी बढ़ावा मिलेगा।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय का खास तौर पर आभार व्यक्त किया गया। समिति ने कहा कि सरकार ने उचित दर विक्रेताओं की समस्याओं और हितों को गंभीरता से लिया है और यह एक अच्छा निर्णय है।

समिति ने भरोसा जताया कि भविष्य में भी सरकार उचित दर विक्रेताओं के हित में ऐसे ही सकारात्मक फैसले लेती रहेगी। इस ज्ञापन के जरिए जिले के सभी उचित दर विक्रेताओं की ओर से मुख्यमंत्री का आभार और धन्यवाद प्रकट किया गया।

अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के आईसीयू में भर्ती, अब कैसी है हालत जानिए

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के कठव में भर्ती कराया गया है। वह महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि के पास एक स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहे थे। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुंबई लाया गया। डॉक्टर गौतम भंसाली की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्ना हजारे को गंभीर वायरल संक्रमण और शरीर में पानी की कमी की शिकायत हुई थी। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बॉम्बे अस्पताल लाया गया। डॉक्टर फिलहाल उनकी कई जांच कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पर आगे का इलाज तय किया जाएगा।

इंजेक्शन से किया बेहोश और करा दिया गर्भपात, सानिया ने खोली पाकिस्तानी क्रिकेटर की पोल, क्रिकेट जगत में भूचाल

(जीएनएस)।

पाकिस्तानी टीम और खिलाड़ी किसी न किसी वजह से अक्सर चर्चा में रहते ही हैं। इंग्लैंड में दो टेस्ट लगातार हारने के बाद टीम में उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच एक खिलाड़ी के निजी जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, जिनसे भूचाल आ गया है।

यह क्रिकेटर इमाद वसीम हैं जिनकी एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी के कुछ ऐसे अनुभव साझा किए हैं, जिनके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

एक यूट्यूब पॉडकास्ट में सानिया ने इमाद और उनके परिवार पर गर्भपात के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2023 में तीसरी बार गर्भवती होने के बाद उन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ गर्भपात का सामना करना पड़ा।

तीसरी प्रेग्नेंसी के बाद बदले हालात

सानिया के मुताबिक, जब उन्हें अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो शुरूआत में इमाद काफी खुश थे। उन्होंने अपनी मां को भी यह खबर बताई थी। इसके बाद परिवार की तरफ से इस प्रेग्नेंसी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि इमाद की मां ने बच्चे को जन्म देने के खिलाफ दबाव बनाया और कथित तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचाने तक की धमकी दी। सानिया के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वह बेहद दबाव और डर की स्थिति में थीं।

सानिया ने सुनाई अस्पताल की कहानी

सानिया ने अस्पताल से जुड़ा अपना अनुभव भी साझा किया। उनका कहना है कि उस समय उनके साथ कोई करीबी व्यक्ति मौजूद नहीं था और उनके दो बच्चे भी उनके साथ थे।

उनका आरोप है कि उन्हें एक इंजेक्शन देने से पहले यह बताया गया कि इसका मकसद उन्हें शांत करना है। सानिया के मुताबिक इसके बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी प्रेग्नेंसी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी सहमति नहीं ली गई थी।

पुराने लखनऊ की सड़कों पर ई रिक्शों का कब्जा, आवागमन मुश्किल

लखनऊ। पुराने लखनऊ में ई रिक्शों की बढ़ती संख्या से भीषण जाम की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के चरक चौराहा, मेडिकल कॉलेज चौराहा और नादान महल तिराहा जैसे प्रमुख स्थानों पर हर समय जाम लगा रहता है। इन क्षेत्रों में पुलिस थाने और चौकियां होने के बावजूद ई रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है।

मेडिकल कॉलेज पुराने लखनऊ का संवेदनशील क्षेत्र है। यहां लखनऊ ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी गंभीर मरीज आते हैं। इसके बावजूद ई रिक्शा चालक मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट के सामने ही अपने रिक्शे खड़े कर देते हैं। इससे एंबुलेंस और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती है। मुख्य गेट के पास अतिक्रमण भी बड़ी समस्या है।

चरक चौराहा : फ्लाईओवर के नीचे अवैध स्टैंड

चरक चौराहे से कुछ दूरी पर चौक थाना और एक पुलिस चौकी भी है। फिर भी फ्लाईओवर के नीचे ई रिक्शों का अवैध स्टैंड चलता है। अगर आपको पाटानाला की ओर से मेडिकल कॉलेज जाना हो तो आप 15 मिनट चरक चौराहे पर ही फंस जाएंगे। जाम बेकाबू होने पर पुलिस थोड़ी देर के लिए कार्रवाई करती है, लेकिन स्थिति फिर जस की तस हो जाती है।

नक्खास : 500 मीटर दूरी तय होती है 20 मिनट में

नक्खास के चिड़िया बाजार से टूड़ियागंज जाने वाले मार्ग पर नादान महल तिराहे पर भी जाम लगना तय है। रविवार को यहां जाम की स्थिति और भी खराब हो जाती है। चिड़िया बाजार से नादान महल तिराहे तक की 500 मीटर की दूरी तय करने में लोगों को 20 मिनट लग जाते हैं। इस तिराहे के आसपास भी पुलिस चौकियां हैं। मगर जाम से कोई राहत नहीं मिलती। तिराहे के पास फल और सब्जी के ठेले सड़क का बड़ा हिस्सा घेर लेते हैं।

क्ट्रैफिक और सिविल पुलिस ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन सेफ राइड के तहत चालकों के सत्यापन किया जा रहा है। अवैध स्टैंड को लेकर भी जांच जारी है।

यूपी के आउटसोर्स कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में भारी वृद्धि, सीएम आज करेंगे घोषणा

(जीएनएस)।

मानदेय बढ़ाने और कई अन्य सुविधाएं दिए जाने का शासनादेश जारी होने के लगभग एक साल बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत तीन लाख से अधिक कार्मिकों का इंतजार बुधवार को समाप्त होगा।

मानदेय वृद्धि के साथ ही इन्हें अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में निगम के कार्यालय का लोकार्पण करने के साथ ही इसके 'लोगो', वेबसाइट व पोर्टल को लांच करेंगे। आउटसोर्स कार्मिकों को बढ़ा मानदेय देने की घोषणा भी करेंगे।

पूर्वाह्न 11 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी जिलों में किया जाएगा। जिलों के कार्यक्रम में वहां तैनात आउटसोर्स कर्मी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आउटसोर्स कर्मियों को बढ़े मानदेय, ईपीएफ, ईएसआइसी सहित अवकाश आदि सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

श्रम विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) के लाभार्थियों को कार्यक्रम में चेक तथा सफाई कर्मियों को किट वितरित किए जाएंगे।

विभागों ने अब तक कुल 2.70 लाख आउटसोर्स कार्मिकों के कार्यरत होने की जानकारी सचिवालय प्रशासन विभाग को दी है। निगमों तथा विभागों से जुड़ी अन्य संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को भी इसमें शामिल किए जाने पर यह संख्या तीन लाख से अधिक होगी। पोर्टल लांच होने के बाद मैनपावर मुहैया कराने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा।

विभाग भी आउटसोर्स कार्मिकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम 20 हजार से 40 हजार रुपये तक मानदेय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 19 सितंबर को निगम का गठन करने के लिए शासनादेश जारी किया गया था।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से होंगी भर्तियां

आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होंगी। हालांकि, श्रेणी-तीन व चार के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय दिया जाएगा।

आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार मानदेय तय किया गया

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में खामियों के बाद बड़ा एक्शन, हर परत की मंजूरी जरूरी; मांगे 21 सुझाव

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में खामियों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे निर्माण में एआइ-एमसी तकनीक के सफल उपयोग के लिए एसओपी बनाने की तैयारी की है।

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। ऑटोमेटेड एंड इंटेलीजेंट मशीन-एडेड कंस्ट्रक्शन (एआई-एमसी) तकनीक के उपयोग के बावजूद लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सामने आई खामियों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दिशा-निर्देशों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बकायदा इस तकनीक के सफल उपयोग के लिए एसओपी बनाने की तैयारी कर ली है।

जिस प्रारूप पर हितधारकों से 21 दिन में सुझाव मांगे गए हैं, उसमें इस बिंदु को भी शामिल किया गया है कि निर्माण की निगरानी के नियुक्त इंडीपेंडेंट इंजीनियर को एआइ-एमसी का निर्णय लिया जा चुका है। सरकार की मंशा है कि जिस तरह की कमियां

के डाटा की जांच के साथ ही किसी भी परत को स्वीकृति दी जाएगी।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की खामियों के बाद मंत्रालय का कदम

अब 20 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में एआइ-एमसी के इस्तेमाल पायलट प्रोजेक्ट यानी लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में सामने आई हैं, वह भविष्य में सामने न आएं।

इसे देखते हुए ही बीते दिनों एनएचएआइ ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने पोर्टल पर एसओपी का प्रारूप भी अपलोड कर दिया है।

इसमें प्रस्तावित किया गया है कि जीपीएस-एडेड मोटर ग्रेडर, इंटेलीजेंट कंपेक्शन रोलर, सिंगल ड्रम, वाइब्रेटरी रोलर आदि के प्रयोग के लिए ठेकेदार को साइट कंट्रोल पाइंट और अस्थायी बेंचमार्क स्थापित करने होंगे।

इंजीनियर हर निर्माण परत की जांच कर देंगे स्वीकृति

एम्बार्कमेंट, सबग्रेड, सब-बेस और बेस लेयर के लिए डिजिटल थ्रीडी माडल बनाकर अथारिटी के इंजीनियर और स्वतंत्र इंजीनियर से उसे स्वीकृत कराना होगा। स्वीकृत ड्राइंग में बदलाव होने पर सात दिन के अंदर माडल में भी बदलाव कर स्वीकृत कराना होगा।

मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है कि निर्माण के दौरान एआइ-एमसी को लागू करने, उसके परिणाम या निष्कर्ष को लेकर पूरे ब्योरे के साथ वचन-पत्र तैयार करना होगा। उसकी जांच प्राधिकरण करेगा।

सीतापुर से सोनीपत कमाने गईं लड़कियां लखनऊ में मिलीं, घास काटना नहीं था पसंद इसलिए छोड़ा घर

सीतापुर की युवती और तीन किशोरियां 27 अगस्त को लापता हुईं।

आर्थिक हालातों से परेशान होकर सोनीपत कमाने के लिए निकली थीं।

पुलिस ने उन्हें लखनऊ से बरामद कर परिवारजनों को सौंपा।

(जीएनएस)।

सीतापुर। घास काटने निकलीं एक गांव की युवती और तीन किशोरियां 27 अगस्त को लापता हो गई थीं। कमजोर आर्थिक हालातों से परेशान होकर उन्होंने सोनीपत में रहकर काम रहे सकरन क्षेत्र के एक युवक के संपर्क किया और कमाने के लिए चली गईं।

गांव के किसी व्यक्ति से पुलिस के सोनीपत के लिए रवाना होने की बात चली तो वह घर के लिए रवाना हो गईं। रविवार देर रात पुलिस ने चारों को लखनऊ से बरामद कर लिया और परिवारजन के सिपुर्द कर दिया है।

युवती और किशोरियां 27 अगस्त की सुबह घास काटने घर से निकली

थीं। काफी देर तक वह वापस नहीं आईं और मोबाइल भी बंद गया। इस पर परिवारजन ने उनकी तलाश शुरू की। पता न लगने पर कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। शुरूआत में पुलिस को उनकी लोकेशन लखनऊ में मिली, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही वे वहां से निकल गई थीं।

चारों लखनऊ से ट्रेन पकड़कर पहले दिल्ली फिर सोनीपत पहुंचीं। यहां सकरन क्षेत्र के युवक के माध्यम से उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया। जानकारी होने पर पुलिस उनकी बरामदगी के लिए सोनीपत के लिए रवाना हो गई। युवतियों की इसकी भनक लगी तो वे घर के लिए चल दीं। पुलिस ने उनको लखनऊ से बरामद कर लिया।

आर्थिक हालातों ने घर छोड़ने को किया मजबूर

युवती और किशोरियों ने बताया परिवार के आर्थिक हालातों ने उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया। प्रतिदिन उन्हें पशुओं के लिए घास काटने जाना पड़ता है। अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। मेहनत करने के बावजूद घर के हालात सुधर नहीं रहे थे। इसके चलते उन्होंने सोचा इतनी मेहनत बाहर करें तो अच्छी कमाई हो जाएगी। इसी के चलते वे सोनीपत काम करने चली गई थीं।

कमाई की लालसा में युवती और किशोरियां सोनीपत गईं थी। घर वापसी करते समय चारों को लखनऊ से बरामद कर लिया गया है। परिवारजन के सिपुर्द कर दिया है। **-भानु प्रताप सिंह, कोतवाल, महमूदाबाद।**

लखनऊ: कार हटाने को लेकर विवाद ने पकड़ा तूल, 8-10 लोगों ने युवक पर किया हमला; पुलिस पर भी सवाल

लखनऊ के कृष्णानगर में सराफा पुलिस चौकी के पास कार हटाने को लेकर विवाद के बाद युवक पर 8-10 लोगों द्वारा हमला किए जाने का आरोप है।

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ में कृष्णानगर थाना क्षेत्र के पूरन नगर स्थित सराफा पुलिस चौकी के पास कार हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित अमित वर्मा का आरोप है कि कबाब-पराठे का ठेला लगाने वाले लक्की ने अपने 8-10 साथियों के साथ मिलकर उस पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। घटना में अमित गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना पास में लगे उउळश कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है।

मामले में पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गाड़ी हटाने के बाद भी दोबारा पहुंचे आरोपी

आलमबाग के विशेष्वर नगर निवासी अमित वर्मा के मुताबिक, वह अपने दो दोस्तों के साथ रात करीब एक बजे सराफा पुलिस चौकी के पास

खड़े थे। इसी दौरान वहां कबाब-पराठे का ठेला लगाने वाले दो लोगों से गाड़ी हटाने को लेकर कहासुनी हो गई।

अमित का कहना है कि विवाद बढ़ता देख उन्होंने अपने दोस्त से गाड़ी हटवा दी। आरोप है कि इसके बाद दोनों लोग वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लक्की 8-10 अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचा।

पीड़ित के मुताबिक, उनके हाथों में लाठी-डंडे और धारदार हथियार थे। इसके बाद सभी ने अमित और उनके साथ मौजूद दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

CCTV में कैद हुई मारपीट

पीड़ित का आरोप है कि हमले में उसके सिर समेत शरीर पर चोटें आईं और वह मौके पर बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने भी खुद को घिरा देखकर वहां से निकलकर मदद लेने की कोशिश की।

अमित के मुताबिक, कुछ देर बाद दोस्त वापस लौटे और उन्हें उपचार के लिए लोकबंधु अस्पताल ले गए। इस पूरी घटना के पास लगे उउळश कैमरों में रिकॉर्ड होने की बात कही जा रही है।

चौकी इंचार्ज की कार्यप्रणाली पर भी सवाल

मामले में पीड़ित ने सराफा पुलिस चौकी के इंचार्ज शिशुपाल सिंह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अमित का आरोप है कि घटना के समय चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था।

पीड़ित के अनुसार, अस्पताल में पुलिस पहुंची तो उनके दोस्तों ने घटना की तहरीर देने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस ने उनकी तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए।

अमित का यह भी आरोप है कि गंभीर मारपीट के मामले में पुलिस ने केवल दो-तीन आरोपियों को पकड़कर शांति भंग की धारा 151 में चालान कर दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया।

पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मांगी निष्पक्ष जांच

अमित वर्मा ने पुलिस कमिश्नरेट के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने उउळश फुटेज के आधार पर घटना की जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है

लखनऊ में है एशिया का पहला महिला कॉलेज, स्थापना के 125 साल पूरे, क्या आप जानते हैं इसका नाम?

(जीएनएस)।

लखनऊ। जिस दौर में बेटियों की शिक्षा समाज के लिए किसी बदलाव से कम नहीं थी, उसी दौर में अमीनाबाद के बीचों-बीच एक कमरे में छह लड़कियों से शुरू हुई छोटी-सी पहल ने इतिहास रच दिया।

18 अप्रैल 1870 को इसाबेला थोबर्न ने जिस स्कूल की नींव रखी थी, वही आगे चलकर आईटी कॉलेज के रूप में महिला शिक्षा की ऐसी मशाल बना, जिसकी रोशनी देश ही नहीं एशिया तक पहुंची। यही संस्थान एशिया का पहला महिला कॉलेज भी बना।

इस गौरवशाली यात्रा में संस्थान ने तमाम बेटियों को शिक्षा, आत्मविश्वास और अपने सपनों को उड़ान देने का मंच दिया। यहां से पढ़कर निकलीं तमाम छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में समाज में कॉलेज का मान बढ़ा रही हैं। मंगलवार को आईटी कॉलेज अपना 125वां संस्थापक दिवस मनाएगा।

1886 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की देखरेख में यहां ललित कला की कक्षाएं शुरू हुई थीं। 1894 में यहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध हो गया। प्राचार्य प्रो. नीरजा मसीह बताती हैं कि 1901 में कॉलेज की संस्थापिका इसाबेला थोबर्न का

निधन हो गया था। उनकी स्मृति में संस्थापक दिवस मनाया जाता है।

आईटी कॉलेज से 1976 से 1978 तक बीएससी बायो की पढ़ाई की। यहां एडमिशन पाना आसान नहीं होता था। पढ़ाई और अनुशासन में इस कॉलेज का कोई जोड़ नहीं था। मैं रजिया हाउस की कैप्टन रही। बेस्ट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वीमेन लीडरशिप अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

-प्रो. निशि पांडेय, प्रोफेसर आफ एमिनेंस, लवि।

जहां छात्रा थीं वहीं शिक्षिका बनीं

यहां कैंपस के कोने-कोने में बिताई हुई यादें हैं। 1988 से 1991 तक बीएससी किया। हास्टल में रहकर पढ़ाई की। साथ में व्यक्तित्व विकास और लीडरशिप सहित काफी चीजें सीखीं। सेना में नौकरी के बाद 2008 में यहां शिक्षिका और अब प्राचार्य बनीं। **-प्रो. नीरजा मसीह, प्राचार्य**

आगे बढ़ने की मिली प्रेरणा

12वीं की मेरिट से यहां 1984 में बीएससी में प्रवेश मिला था। डेविडसन मैम बाटनी और डा. हक सर जूलाजी पढ़ाते थे। बहुत अच्छा माहौल था। छात्राओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता था। मैं सरोजनी हाउस की वाइस प्रेसीडेंट भी रही। **-प्रो.फरजाना मेहंदी, प्रति कुलपति, एरा यूनिवर्सिटी**

सपने पूरे करने का हौसला मिला

1990 से 1995 तक यहां 12वीं से लेकर बीए तक पढ़ाई पूरी की। शिक्षकों ने सपने पूरे करने, अपने आपको समझने और गलतियों से सीखने का मौका दिया। कॉलेज की बहुत सी यादें हैं। मेरी पहली किताब का दूसरे संस्कार का विमोचन इसी कॉलेज में हुआ। **-के.राशि बडालिया कुमार, फैकल्टी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।**

ओडिशा से लखनऊ जा रहा 56 किलो गांजा पकड़ा, तस्कर गिरफ्तार, कार के अंदर 53 बंडलों में छिपाया गया था

(जीएनएस)।

लखनऊ, पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये है। तस्करी में प्रयुक्त वेरना कार, मोबाइल फोन और एटीएम निकासी की पर्ची समेत कुल बरामदगी की कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है। कार की तलाशी में डिकी से खाकी टेप में लिपटे 53 बंडलों में गांजा बरामद हुआ।

ओडिशा से लखनऊ के मटियारी और चिनहट क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने जा रहे अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के एक आरोपी को दुद्धी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 53 बंडलों में 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये है। तस्करी में प्रयुक्त वेरना कार, मोबाइल फोन और एटीएम निकासी की पर्ची समेत कुल बरामदगी की कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस लाइन सभागार में एसपी

अभिषेक वर्मा ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन शुद्धि के तहत दुद्धी कोतवाल प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी नागेश सिंह के नेतृत्व में टीम म्योरपुर तिराहा पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। सूचना पर विंढमगंज की ओर से आ रही सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया। चालक कार को तेज गति से रजखड़ की ओर लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर रजखड़ घाटी के पास घेराबंदी कर कार रोक ली। तलाशी में डिकी से खाकी टेप में लिपटे 53 बंडलों में गांजा बरामद हुआ।

पकड़े गए आरोपी की पहचान हरदोई के अलीपुर निवासी ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह के रूप में हुई। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल और 10 हजार रुपये की एटीएम निकासी संबंधी पर्ची भी मिली। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साथियों के साथ ओडिशा के बोध क्षेत्र से गांजा खरीदकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी व चिनहट में सप्लाई करता था। गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप कॉल से संपर्क करते थे। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

मध्य प्रदेश

आरोपी के खिलाफ दुद्धी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ लखनऊ और बाराबंकी में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज हैं।

87 की उम्र में समाजसेवा का जज्बा, जीके सेठ ने 300 लोगों की आंखों को दी रोशनी; नेत्रदान बना जीवन का संकल्प

(जीएनएस)।

लखनऊ। 87 वर्ष की आयु.. जीवन का ऐसा पड़ाव जब अधिकांश लोग दुनियादारी से मुक्त होकर शांति की खोज में लग जाते हैं। घर-परिवार के प्रति भी रुझान सीमित हो जाता है। इस उम्र में भी अगर कोई समाजसेवा के प्रति समर्पित है तो उससे प्रेरित होना स्वाभाविक है। पेपर मिल कालोनी निवासी 87 वर्षीय जीके सेठ ऐसे ही विरले हैं।

नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक करना और जरूरतमंदों की मदद करना उनके जीवन का संकल्प बन चुका है। बैंक में नौकरी के दौरान वह अक्सर हजरतगंज में दृष्टिबाधित लोगों को सड़क पार करते देखते थे। उन्हें देखकर वह स्वयं को उनकी जगह रखकर सोचते और कुछ करने की इच्छा रखते थे।

नौकरी की व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो सका, लेकिन यह कसक मन में बनी रही। वर्ष 1997 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने समाजसेवा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों से

प्रभावित जीके सेठ कहते हैं कि 'नर सेवा नारायण सेवा' का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

अब तक वह 300 से अधिक लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर चुके हैं। उनका मोबाइल फोन 24 घंटे खुला रहता है। नेत्रदान की सूचना मिलने पर वह किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के चिकित्सकों के साथ संबंधित परिवार तक पहुंचते हैं। परिवार को धन्यवाद देने के साथ वह नेत्रदान के महत्व को भी समझाते हैं।

बोतल में रखते हैं पेट्रोल

जीके सेठ स्कूटर की डिक्की में करीब 250 ग्राम पेट्रोल भी रखते हैं। रास्ते में पेट्रोल खत्म होने से परेशान किसी वाहन चालक को वह यह पेट्रोल निःशुल्क दे देते हैं। युवाओं को भी वह वाहन में रिजर्व पेट्रोल की व्यवस्था रखने की सीख देते हैं।

स्कूटर बना जागरुकता का माध्यम

नेत्रदान की फाइल हाथ में लेकर चलने वाले सेठ ने अपने स्कूटर पर भी 'नेत्रदान महादान' का लोगो लगा रखा है। ट्रामा सेंटर के पास सर्दियों में वह रैनबसेरा भी चलाते हैं।

राजाजीपुरम, ऐशबाग और राजेंद्रनगर में जन स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पत्नी वीना सेठ के साथ बेटा मनीष, बेटी सीमा, दामाद शैलेंद्र, बहू शिखा, पोता यश और पौत्री गौरी भी उनका सहयोग करते हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पाक-चीन को खरी-खरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानि एससीओ से उन देशों का मुकाबला करने का आग्रह किया जो आतंकवाद का इस्तेमाल सरकार की नीति के तौर पर करते हैं। मजे की बात तो यह है कि जिस वक्त आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण देना शुरू किया, उस वक्त वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मौजूद थे। दरअसल पाकिस्तान आतंकी संगठन को अपनी सेना का सहयोगी संगठन मानता है। पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी आईएसआई के निर्देशन में वहां के आतंकी संगठन आतंकी गतिविधियों का संचालन करते है। आतंकियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान सरकार दुर्दान्त आतंकी सरगनाओं को गैर-सरकारी संगठन यानि एनजीओ का संचालक साबित करती है। दुनिया भर में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों को इस तरह पेश करती है कि यह संगठन गरीब दुखिया की सेवा कर रहे हैं। यद्यपि पाकिस्तान के इस झूठ को पूरी दुनिया समझती भी है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है।

आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ एफएटीएफ कई बार पाकिस्तान को निगरानी सूची में रख चुका है। लेकिन अपने चुछ मददगार देशों जैसे चीन और तुकी की मदद से फिर बाहर आ जाता है। भारत ने पाकिस्तान का वूटनीतिक बहिष्कार कर रखा है इसीलिए उससे किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। कई ऐसे अवसर आए जब पाकिस्तान की सरकार ने आईएसआई और सेना के दबाव में न आने के संकेत दिए और दोनों देशों के बीच वार्ता की तैयारी भी हुई किन्तु आईएसआई नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सहयोगात्मक हों। इसीलिए वार्ता के ठीक पहले आतंकी घटनाएं करा देती है ताकि दोनों देशों में शत्रुता का माहौल बन जाए। पाकिस्तान की सेना जानती है कि यदि भारत के साथ उसके संबंध सुधर जाएंगे तो उसकी यानि पाक सेना की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जब कभी दोनों देशों में समझौतावादी माहौल का वातावरण बना तो पाक सेना और आईएसआई ने माहौल को शत्रुवत बनाने के उद्देश्य से भारत के खिलाफ खूनी हथवंडा अपनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी खरी-खरी सुना दी। कारण कि पाकिस्तान तो आतंकियों को पालता पोषता है किन्तु चीन उनको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संरक्षण देकर पाकिस्तान पर एहसान जताता है ताकि पाक सेना व सरकार चीन के निवेश का पूरी तरह ध्यान रखे। जब कभी भी पाकिस्तान के इन दुर्दान्त आतंकियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव आया तो चीन वीटो के हथियार का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के नायक आतंकियों को बचा लेता है। बहरहाल भारत के प्रधानमंत्री के लिए पाक के पालित आतंकवादी विश्व शान्ति के लिए चुनौती हैं तो उन्हें जो संरक्षण देते हैं वे भी उतने ही दोषी हैं। इस तरह भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान दोनों की हकीकत बताई।

पीएम मोदी की अपील के बाद भी क्यों नहीं टूटेगा सोने का मोह? भारत की कुंडली में दिखा बड़ा कारण

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि जरूरत न हो तो सोना न खरीदें. विदेश में छुट्टियां और डेस्टिनेशन वेडिंग भी टालें. इसके पीछे मकसद विदेशी मुद्रा बचाना और देश के भीतर खर्च बढ़ाना है. लेकिन त्योहारों और शादियों से ठीक पहले क्या भारतीय परिवार सचमुच सोने से दूरी बना लेंगे?

भारत की कुंडली इसका सीधा जवाब नहीं देती. 2 सितंबर 2026 को शुक्र अपनी तुला राशि में आ रहा है. इससे आभूषण खरीदने की इच्छा बढ़ सकती है. दूसरी ओर, धन भाव पर मंगल और शनि का दबाव बता रहा है कि लोगों की पसंद और जेब के बीच बड़ा अंतर रहेगा. यानी बाजार से खरीदार गायब नहीं होंगे, लेकिन उनके खरीदने का तरीका बदल सकता है.

मोदी ने सोना कम खरीदने के लिए क्यों कहा?

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेश से मंगाता है. इसका भुगतान डॉलर में होता है. सोने का आयात बढ़ने पर देश का आयात बिल और व्यापार घाटा बढ़ता है. इससे रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ सकता है.

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बढ़कर करीब 71.98 अरब डॉलर हो गया था. यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले लगभग 24 प्रतिशत अधिक था. ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील केवल लोगों की निजी खरीद से जुड़ी नहीं है. इसके पीछे देश से बाहर जा रहे डॉलर को बचाने की चिंता भी है.

मोदी ने लोगों से गैर-जरूरी सोना न खरीदने के साथ विदेशी यात्राएं और विदेश में होने वाली शादियां टालने की बात कही है. उनका जोर पैसा देश के भीतर खर्च करने और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने पर है.

2 सितंबर के बाद शुक्र क्यों बढ़ाएगा मुश्किल?

भारत की मूल कुंडली वृषभ लग्न की है. इसमें शुक्र लग्नेश होने के साथ छठे भाव का स्वामी भी है. इसलिए शुक्र देश के रहन-सहन, खरीदारी की आदत, सुख-सुविधा और बाजार की मांग पर असर डालता है.

2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में आकर भारत की कुंडली के छठे भाव में पहुंचेगा. तुला शुक्र की अपनी राशि है. मजबूत शुक्र सोना, गहने, फैशन और शादी से जुड़ी खरीद की इच्छा बढ़ा सकता है.

लेकिन छठा भाव कर्ज, किस्त, प्रतिस्पर्धा और देनदारी से भी जुड़ा है. इसका अर्थ है कि महंगा सोना खरीदने के लिए ग्राहक नए रास्ते खोज सकते हैं. बाजार में पुराना सोना देकर नया गहना लेने, किस्त पर खरीद, कम वजन वाली ज्वेलरी और मेकिंग चार्ज पर छूट जैसी स्कीम बढ़ सकती हैं.

लोग सोना खरीदना पूरी तरह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बार में खरीदे जाने वाले सोने का वजन घट सकता है.

मजबूत शुक्र की दृष्टि विदेशी खर्च पर

तुला राशि में बैठा शुक्र भारत की कुंडली के 12वें भाव मेष को देखेगा. ज्योतिष में 12वां भाव आयात, विदेशी भुगतान और देश से बाहर जाने वाली मुद्रा से जुड़ा माना जाता है.

यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संकेत है. सरकार सोने की खरीद घटाकर विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है. दूसरी तरफ मजबूत शुक्र का प्रभाव विदेशी खर्च वाले भाव पर पड़ रहा है. इससे पता चलता है कि सोने और विलासिता से जुड़ा विदेशी भुगतान जल्दी काबू में आना आसान नहीं होगा.

सरकार की अपील निवेश के लिए होने वाली बड़ी खरीद को रोक सकती है. हालांकि शादी और त्योहार से जुड़ी खरीद पर इसका असर सीमित रहने की संभावना है.

तमिलनाडुः टीवीके के मंत्री क्यों देख रहे जोसेफ विजय में पीएम का चेहरा?

"जो लोग सुबह या शाम, घड़ी देखे बिना काम करते हैं, वो ही भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री होंगे." तमिलनाडु सरकार में मंत्री सरथकुमार ने 18 अगस्त को विधानसभा में यह बयान दिया.

(जीएनएस)।

टीवीके के कई मंत्री मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को "भविष्य का प्रधानमंत्री" बता रहे हैं. इस पर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगौर ने कहा है कि टीवीके के लोग अभी भी प्रशंसक मंडली वाली मानसिकता में जी रहे हैं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, विजय के नेतृत्व वाली टीवीके पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो उस वक़्त कांग्रेस ने सबसे पहले अपने पांच विधायकों का समर्थन देने की पेशकश की थी.

उस समय पनैयूर में टीवीके नेता विजय से मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेता गिरीश चोडांकर ने घोषणा की थी कि "स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी टीवीके के साथ गठबंधन जारी रहेगा."

10 मई को जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे. विजय की सरकार में कांग्रेस को दो मंत्री पद दिए गए.

इस बीच, पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को 'प्रधानमंत्री बनने वाले नेता' के तौर पर उनके मंत्री जिस तरह से पेश कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के भीतर कई तरह की चचाएं शुरू हो गई हैं.

18 अगस्त को विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री सरथकुमार ने कहा, "पीएम विजय भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे."

22 अगस्त को विरुधुनगर में आयोजित एक निजी रोजगार मेले में समाज कल्याण मंत्री जगदीश्वरी शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने कहा, "आज के सीएम, कल के पीएम. भविष्य में सिर्फ हमारी ही सरकार होगी."

इसके बाद एक जनसभा में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन ने कहा, "मुख्यमंत्री सिर्फ तमिलनाडु पर शासन करने वाली ताकत नहीं हैं, बल्कि वह भविष्य के भारत पर शासन करने में सक्षम ताकत के रूप में उभर सकते हैं."

तमिलनाडु के मत्स्य पालन मंत्री श्रीनाथ ने एक मंच पर कहा, "मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, उन पर फोकस रहता है. कल दिल्ली में भी उनका राज हो सकता है."

तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के टीवीके विधायक श्रीनिवास सेतुपति ने एक जनसभा में कहा, "2029 में जोसेफ विजय के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनना संभव है. हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."

उन्होंने यह भी कहा, "तीन साल में तमिलनाडु बेहतर हो जाएगा. उसके बाद भारत बेहतर हो जाएगा. अगर भारत को बेहतर होना है तो एक नेता चाहिए. ऐसे एकमात्र नेता हमारे मुख्यमंत्री हैं."

टीवीके के मंत्रियों की ओर से लगातार दिए जा रहे ऐसे बयानों को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर से पत्रकारों ने सवाल किया.

उन्होंने कहा, "प्रशंसक मंडली वाली मानसिकता में रहने वाले लोगों को बदला नहीं जा सकता."

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, "वे परिसीमन लाने की योजना बना रहे हैं. हम इस लड़ाई में उलझे हैं."

वरिष्ठ पत्रकार श्याम कहते हैं, "मणिकम टैगोर की आलोचना से पता चलता है कि टीवीके के पदाधिकारी और मंत्री अभी तक राजनीति में परिपक्व नहीं हुए हैं."

वरिष्ठ पत्रकार मालान कहते हैं, "जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना कांग्रेस के लिए असहज स्थिति पैदा करेगा. लेकिन यह बात सिर्फ टीवीके के लोग ही उठा रहे हैं. पार्टी नेतृत्व की ओर से इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है."

'राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश'

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने के पीछे कई रणनीतियां हो सकती हैं.

श्याम कहते हैं, "राज्य की राजनीति में जीत हासिल कर सरकार बनाने के बाद टीवीके अपने नेता विजय को सिर्फ. राज्य के नेता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है."

फिल्मी पृष्ठभूमि से राजनीति में आए विजय के प्रशंसकों का ज़िक्र करते हुए वह कहते हैं, "उनका मानना है कि इससे प्रशंसकों को सक्रिय राजनीतिक कार्यकताओं में बदलने और पार्टी के आधार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरणा मिलेगी."

श्याम आगे कहते हैं, "कांग्रेस समेत गठबंधन सहयोगियों के साथ समझौते में रहते हुए भी टीवीके के महत्व और बातचीत की ताकत को बढ़ाकर दिखाने के लिए इसे एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है."

वरिष्ठ पत्रकार मालान भी इसी तरह की बात कहते हैं, "पार्टी के लोग चाहते हैं कि टीवीके को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हो. इसका उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय मीडिया टीवीके को केवल एक राज्य पर शासन करने वाली पार्टी के रूप में न देखे." मालान ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में पहले भी राज्य की पार्टियों के नेताओं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिशें हुई हैं.

2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने 'मोदी या लेडी' का नारा दिया था. इससे पहले दिसंबर 2013 में हुई एआईएडीएमके की आम परिषद की बैठक में जयललिता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का प्रस्ताव पारित किया गया था.

हालांकि, जयललिता ने कहा था कि यह पार्टी का फैसला है और उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है.

2014 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने तमिलनाडु ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी.

इस मामले में एक अलग नजरिया पेश करते हुए श्याम कहते हैं, "2029 के लोकसभा चुनाव के दौरान अगर टीवीके जीत हासिल करती है और उसके सांसद चुने जाते हैं, तो कुछ चीजें होने की संभावना है."

उनका कहना है कि इसके पीछे दीर्घकालिक योजना यह हो सकती है कि टीवीके राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले तय करने वाली ताकत के रूप में उभरे.

मालान कहते हैं, "टीवीके का मानना है कि उसे जनता का समर्थन हासिल है, इसलिए वह राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण ताकत बनेगी."

वह कहते हैं, "टीवीके का यह नारा लोकसभा चुनाव में ज्यादा असर नहीं डालेगा. प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे."

मालान कहते हैं, "फिलहाल टीवीके इंडिया गठबंधन में नहीं है. साल 2029 में इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियां राहुल गांधी को स्वीकार करेंगी या नहीं, यह महत्वपूर्ण है. इसके लिए अभी समय है, इसलिए 'प्रधानमंत्री विजय' के नारे को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है." टीवीके का क्या कहना है? टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक एडवोकेट सत्यकुमार से पूछा कि क्या इस तरह की बयानबाजी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की रणनीति के तहत की जा रही है. वह कहते हैं, "जोसेफ विजय का प्रधानमंत्री बनना समय की मांग है. खास तौर पर भारत के मतदाताओं में जेन-जी पीढ़ी के लोगों की संख्या काफी है. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय उनकी पसंद हैं." वह कहते हैं, "वो एक मजबूत नेता की उम्मीद कर रहे हैं. राज्य की मौजूदा पार्टियों में मजबूत नेता नहीं हैं. यह विजय के लिए फायदेमंद साबित हुआ है." जब उनसे पूछा गया कि "क्या उत्तर भारत में टीवीके के नेता को स्वीकार किया जाएगा?" उन्होंने कहा, "जोसेफ विजय के भाषणों का उत्तर भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर उन्हें फैलाया जा रहा है.

मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई से वक्फ फंड तकः क्या विजय सरकार भी 'फ्रीबी मॉडल' में फंस रही? तमिलनाडु पर कितना बोझ?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ। अभिनेता से नेता बने विजय यानी थलपति विजय की पार्टी TVK ने सत्ताधारी DMK को हरा दिया। चुनाव से पहले विजय ने वादा किया था कि उनकी सरकार बाकी पार्टियों से अलग होगी। लेकिन सत्ता में आए सिर्फ चार महीने हुए हैं, और सरकार का रुख कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है।

हाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुस्लिम छात्राओं की स्नातक पढ़ाई की पूरी फीस उठाने, वक्फ छात्रवृत्ति बढ़ाने, चेन्नई में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नया कॉलेज खोलने और वक्फ व ईसाई धार्मिक संपत्तियों पर कमाई वाली परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने का ऐलान किया। इसके साथ ही मुफ्त गैस सिलेंडर और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं भी सामने आई हैं। सवाल यही है कि क्या यह सामाजिक कल्याण है या ऐसी मुफ्त योजनाओं का रास्ता, जिसका बोझ आगे चलकर राज्य के खजाने और आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा?

मुस्लिम लड़कियों की फ्री पढ़ाई से लेकर वक्फ फंड तक, समझिए पूरा मामला

27 अगस्त को तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ए एम शाहजहां ने ऐलान किया कि सरकारी कोटे से एडमिशन लेने वाली हर मुस्लिम लड़की की अंडर-ग्रेजुएट पढ़ाई की पूरी फीस अब राज्य सरकार भरेगी। यह स्कीम सरकारी, सरकारी-सहायता प्राप्त और सेल्फ-फाइनेंस कॉलेजों में लागू होगी। इसके लिए शुरूआत में 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इतना ही नहीं, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की स्कॉलरशिप स्कीम को भी बढ़ाया गया है। पहले यह क्लास 1 से 8 तक की मुस्लिम लड़कियों को मिलती थी, अब क्लास 9 और 10 की लड़कियों को भी हर साल 2000 रुपये मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे 41,384 मुस्लिम स्कूली लड़कियों को फायदा होगा, और इस पर कुल 8.28 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मंत्री शाहजहां ने यह भी बताया कि चेन्नई में एक नया 'माइनॉरिटीज वुमेन्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज' बनेगा, जिसके लिए 2.45 करोड़ रुपये की शुरूआती ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने कहा, "राजधानी में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड नया कॉलेज खोलेगा। साथ ही राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये का एक रिवॉल्विंग फंड बनाएगी, जिससे

मुस्लिम वक्फ और ईसाई धार्मिक संपत्तियों पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और मैरिज हॉल जैसी कमाई वाली संपत्तियां बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा।"

यहां से राजनीतिक सवाल शुरू होता है। सरकार का तर्क शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का है। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि ऐसी मदद को सिर्फ धर्म के आधार पर देने के बजाय परिवार की आर्थिक स्थिति को आधार क्यों न बनाया जाए।

वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ का फंड और नया हेडक्वार्टर भी

सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए नया हेडक्वार्टर भी बनेगा, जिसकी लागत करीब 40 करोड़ रुपये आंकी गई है। साथ ही वक्फ बोर्ड को मिलने वाला सालाना प्रशासनिक अनुदान भी बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ₹100 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बनाने की भी घोषणा की है। इससे मुस्लिम वक्फ और ईसाई धार्मिक संपत्तियों पर आय पैदा करने वाली परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना है।

इन पैसों का इस्तेमाल व्यावसायिक परिसरों, विवाह भवन जैसी कमाई वाली संपत्तियां विकसित करने में किया जा सकता है। इसके अलावा चेन्नई में वक्फ बोर्ड के जरिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कला और विज्ञान कॉलेज खोलने की योजना है। इसके लिए शुरूआती ₹2.45 करोड़ की राशि बताई गई है। यानी सरकार की अल्पसंख्यक नीति सिर्फ छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षा, संस्थान और संपत्ति विकास तक का पूरा पैकेज दिखाई देता है।

हर नवजात बच्चे को सोने की अंगूठी, सरकारी खजाने पर नया बोझ

द्रमुक के चुनावी घोषणापत्र में सबसे महंगा वादा था सरकारी अस्पतालों में जन्मे बच्चों को 8 ग्राम यानी एक सोवरेन सोना देना। सरकार बनते ही विजय ने 'थाईमन थंगा मोथिरम' स्कीम शुरू की, जिसमें राज्य में सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों को 1 ग्राम की 22 कैरेट सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस पर हर साल 756 करोड़ रुपये खर्च होंगे, यानी करीब 4.42 लाख अंगूठियां बांटी जाएंगी। यह स्कीम 22 जून 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी खुद उट विजय के जन्मदिन से, और इसे औपचारिक रूप से 15 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

सवाल यह है कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही यह फायदा क्यों?

अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही होती है? क्या राज्य की हिंदू बेटियों के परिवार इतने संपन्न हैं कि उन्हें सरकारी मदद की जरूरत ही नहीं?

सरकार ने सभी गरीब लड़कियों के लिए फीस माफी की स्कीम बनाने की बजाय सिर्फ एक धर्म को क्यों चुना, यह सवाल भी उठ रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस तरह की धर्म आधारित स्कीमें एक तरह से यह संदेश देती हैं कि किसी खास मजहब को मानने पर ही राज्य से ज्यादा फायदा मिलेगा। जबकि राज्य के खजाने में हिंदू टैक्सपेयर्स और मंदिरों का भी बड़ा योगदान होता है।

यहां एक बात साफ समझना जरूरी है। किसी कमजोर वर्ग को सरकारी मदद देना अपने आप में गलत नहीं है। सवाल यह है कि लाभार्थी तय करने का आधार क्या हो और सरकार के पास लंबे समय तक इन योजनाओं को चलाने की वित्तीय क्षमता कितनी है।

तमिलनाडु की अपनी वित्तीय रिपोर्ट इस बहस को और गंभीर बना देती है। जून 2026 में जारी राज्य के वित्तीय श्वेतपत्र के मुताबिक, राज्य की कुल देनदारियां करीब ₹13.18 लाख करोड़ तक पहुंच गई हैं। इसमें राज्य का प्रत्यक्ष कर्ज और सार्वजनिक उपक्रमों की देनदारियां शामिल हैं। प्रत्यक्ष सरकारी कर्ज करीब ₹10 लाख करोड़ बताया गया है।

राजस्व घाटा भी ₹78,324 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं 2025-26 में ब्याज भुगतान करीब ₹67,050 करोड़ रहा। इसका मतलब है कि सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा पहले से ही पुराने कर्ज और ब्याज की तरफ जा रहा है।

चेन्नई का दूसरा एयरपोर्ट अटका, विकास पर सीधा असर

एक तरफ फ्री स्कीमों की बरसात हो रही है, दूसरी तरफ विजय सरकार ने पारांदुर में बनने वाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, जबकि उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका था। यह फैसला विरोध कर रहे किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए लिया गया। लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट पर हर साल करीब 3 करोड़ यात्री आते हैं, और आने वाले सालों में यह क्षमता पूरी तरह भर जाएगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स की संस्था एफएऊअक ने भी कहा है कि इस फैसले से चेन्नई को बड़े निवेश और उद्योगों के हाथ से निकलने का खतरा है, क्योंकि नई जगह ढूंढना, जांच-पड़ताल और मंजूरी लेने में सालों लग जाएंगे।

बिजली बोर्ड पर 2.47 लाख करोड़ का कर्ज, फिर भी टैरिफ नहीं बढ़ेगा

जून 2025 में जारी हुए एक व्हाइट पेपर में बिजली मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने खुद माना कि तमिलनाडु के पावर सेक्टर पर 2.47 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जो राज्य के कुल पब्लिक सेक्टर कर्ज का 77.6% हिस्सा है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन को हर महीने भारी नकदी की कमी झेलनी पड़ रही है, जिससे सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपये का गैप बन रहा है। इसके बावजूद सरकार ने कहा है कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और किसानों को मुफ्त बिजली जारी रहेगी।

फ्री सिलेंडर, फ्री बस यात्राः फ्रीबीज की लिस्ट लंबी होती जा रही है

अगस्त 2026 के आखिर में उट विजय ने 'अन्नपूर्णी सुपर सिक्स' स्कीम के तहत 2.5 लाख रुपये सालाना आय से कम वाले परिवारों को साल में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया। इससे करीब सवा करोड़ परिवारों को फायदा होगा, लेकिन इस पर हर साल 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। साथ ही ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा और महिलाओं के लिए 'वेत्री पयाना थिट्टम' स्कीम का दायरा भी बढ़ा दिया गया है, अब महिलाएं एक्सप्रेस, छरर और डीलक्स बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी।

राज्य पर 13.18 लाख करोड़ का कर्ज, फिर भी मुफ्त योजनाओं की बहार

इसी साल जून में सरकार ने खुद एक व्हाइट पेपर जारी करके बताया कि तमिलनाडु पर कुल 13.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें से 10 लाख करोड़ सीधे राज्य का कर्ज है और बाकी 3.18 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर कंपनियों की देनदारी है। हर नागरिक के सिर पर औसतन 1.29 लाख रुपये का कर्ज है। राजस्व घाटा भी रिकॉर्ड 78,324 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो ऋऊड का करीब 2.2% है। सालाना ब्याज ही 67,050 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जो राज्य के कुल पूंजीगत खर्च से भी ज्यादा है।

तमिलनाडु का राजस्व घाटा पहले से ही सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने में उलझा हुआ है। ऐसे में सोने की अंगूठी हो या धार्मिक अल्पसंख्यक स्कीमें, हर नई घोषणा राज्य पर बोझ बढ़ा रही है। भले ही सरकार इसे चुनावी वादे पूरे करने की मजबूरी बताए, लेकिन आज की मुफ्त सौगातें कल राज्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी कर्ज. बनकर सामने आ सकती हैं।

बिहार : मछली खाने से क्यों किया गया मना? सरकार की एडवाइजरी की क्या है वजह

(जीएनएस)।

बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ की मार झेल रहे हैं। नदियों और जलाशयों का पानी बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने मछली खाने को लेकर खास एडवाइजरी जारी की है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मत्स्य प्रभाग ने लोगों से बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने की अपील की है।

विभाग के मुताबिक, नेपाल से आए बाढ़ के पानी के साथ कुछ इलाकों में अज्ञात और असामान्य मछलियां पहुंचने की सूचना मिली है। इनके सेवन से कुछ लोगों के बीमार पड़ने की भी खबर है। ऐसे में सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है।

नेपाल में आई बाढ़ के बाद पानी बिहार के कई इलाकों तक पहुंचा है। इसी बाढ़ के पानी के साथ कुछ क्षेत्रों में अज्ञात और असामान्य प्रकार की मछलियां पहुंचने की सूचना मिली है। मत्स्य विभाग के अनुसार, ऐसी मछलियों के सेवन के बाद कुछ लोगों के बीमार पड़ने की जानकारी भी सामने आई है। यही वजह है कि विभाग ने लोगों को बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियां खाने से फिलहाल बचने की सलाह दी है।

विभाग ने बताया कि बाढ़ के दौरान तालाबों, नदियों, झीलों और दूसरे जलाशयों से मछलियां निकलकर दूर तक फैल जाती हैं। इस दौरान उनका संपर्क गंदी नालियों, मृत जानवरों और दूसरे प्रदूषित पदार्थों से हो सकता है। ऐसे पानी में रहने से मछलियां जीवाणु, विषाणु और कवक जैसे रोग पैदा करने वाले कारकों से दूषित हो सकती हैं। इसलिए बाढ़ के दौरान पकड़ी गई मछलियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

सरकार की एडवाइजरी में लोगों को तब तक बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों का सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है, जब तक वातावरण स्थिर नहीं हो जाता। विभाग के मुताबिक, प्राकृतिक रूप से गंदगी और रोग फैलाने वाले कारकों के समाप्त होने तक सावधानी जरूरी है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बिना पहचान और संबंधित विभाग की पुष्टि के किसी भी अपरिचित मछली को खाने से बचें।

बाजार में बेचने पर भी रोक

मत्स्य विभाग ने केवल लोगों को मछली खाने से बचने की सलाह नहीं दी है, बल्कि बाढ़ के पानी से पकड़ी गई मछलियों को बाजार में बेचने से भी मना किया है। विभाग का कहना है कि किसी अपरिचित मछली की पहचान और उसके सुरक्षित होने की पुष्टि जरूरी है। इसलिए मछली विक्रेताओं और आम लोगों को भी ऐसी मछलियों की खरीद-बिक्री से बचने की सलाह दी गई है।

जानकीपुरम में गूंजेगा किसानों के हक का बिगुल, 7 सितंबर को महापंचायत

कथित पुलिस उत्पीड़न और अन्याय के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन ने खोला मोर्चा।

(जीएनएस)।

लखनऊ। किसानों से जुड़े कथित अन्याय, उत्पीड़न और पुलिस कार्रवाई के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन ने राजधानी लखनऊ में आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन की ओर से 7 सितंबर 2026, सोमवार को सुबह 10:30 बजे जानकीपुरम थाने पर विशाल किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी।

महापंचायत की तैयारियों को लेकर 30 अगस्त को टेढ़ी पुलिया स्थित संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय में आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ मंडल के विभिन्न जनपदों से पहुंचे पदाधिकारियों ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से जानकीपुरम थाने पर महापंचायत

आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

संगठन का आरोप है कि कई मामलों में किसानों को कथित तौर पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं, पुलिस कार्रवाई को लेकर भी किसानों में नाराजगी है। संगठन का कहना है कि इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाने और किसानों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है।

महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन ने व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष मो. हलीम ने पदाधिकारियों और कार्यकताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज करने की अपील की।

मो. हलीम ने कहा कि किसानों के सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए संगठन मजबूती से आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी समस्याओं को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाएगा।

संगठन की ओर से लखनऊ मंडल के सभी जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं से निर्धारित समय पर जानकीपुरम पहुंचने का आ'ान किया गया है। महापंचायत को लेकर संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन का दावा है कि यह कार्यक्रम किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों की आवाज को मजबूती से उठाने का महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

सपा में शामिल होकर बीसलपुर लौटे रत्नेश गंगवार, रोड शो में दिखाया दम

(जीएनएस)।

बीसलपुर। सपा में शामिल होने के बाद लखनऊ से लौटे डॉ. रत्नेश गंगवार का मंगलवार को बीसलपुर पहुंचने पर कार्यकताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। नगर में रोड शो निकालकर उन्होंने सपा के समर्थन में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बीसलपुर-शाहजहांपुर और बीसलपुर-पीलीभीत मार्ग पर रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे।

चठिया सेवाराम, रोहनिया, गलेदा, चीनी मिल और पीलीभीत मार्ग समेत करीब एक दर्जन स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। बीसलपुर की सीमा में पहुंचते ही समर्थकों ने पुष्पवर्षा कर डॉ. गंगवार का स्वागत किया। इसके बाद ग्राम खनंका से रोड शो शुरू हुआ। काफिले में 400 से अधिक चार पहिया और दोपहिया वाहन शामिल रहे। सैकड़ों कार्यकर्ता सपा के समर्थन में नारे लगाते हुए कैंप कार्यालय तक पहुंचे, जहां रोड शो का समापन हुआ।

इसके बाद पत्रकार वार्ता में डॉ. रत्नेश गंगवार ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि विकास के बड़े-बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी तस्वीर उन दावों से अलग है। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सुविधाओं और रोजगार जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। उन्होंने क्षेत्र के मौजूदा जनप्रतिनिधि के कार्यों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही रोडवेज बस स्टैंड समेत क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। डॉ. गंगवार ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान उन्हें प्रत्याशी बनाएगा और वह क्षेत्र में सपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

माल व्यापार मंडल की नई जिम्मेदारियां तय, गोपाल गुप्ता को फिर मिली अध्यक्ष पद की कमान

(जीएनएस)।

माल। माल के व्यापारियों को संगठित करने और उनके हितों को प्रमुखता से उठाने के उद्देश्य से माल उद्योग व्यापार मंडल में पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गईं। संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से गोपाल गुप्ता को पुनः अध्यक्ष चुना गया।

संगठन के संरक्षक विजय कुमार सिंह चौहान, संस्थापक सदस्य उमाशंकर त्रिपाठी, उप संरक्षक राज प्रताप सिंह और अनिल गुप्ता की उपस्थिति में अध्यक्ष पद के लिए

गोपाल गुप्ता के नाम पर सहमति बनी। इसके बाद उन्हें दोबारा संगठन की कमान सौंपी गई। वहीं युवाओं को संगठन में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से युवा व्यापार मंडल की जिम्मेदारी भी तय की गई। अभिषेक सोनी को युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष तथा शुभम गुप्ता को महामंत्री बनाया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों के मनोनयन के बाद व्यापारियों ने उनका स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर संगठन को मजबूत बनाने, व्यापारियों की समस्याओं को एकजुट होकर उठाने और व्यापारिक हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों

सपा में शामिल होकर लौटे रत्नेश गंगवार, बीसलपुर में जोरदार स्वागत; रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़

400 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ निकला रोड शो, जगह-जगह हुआ पुष्पवर्षा से स्वागत

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद लखनऊ से मंगलवार को बीसलपुर लौटे डॉ. रत्नेश गंगवार का कार्यकताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बीसलपुर की सीमा में प्रवेश करते ही जगह-जगह समर्थकों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद ग्राम खनंका से रोड शो शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।

चठिया सेवाराम, रोहनिया, गलेदा, चीनी मिल और पीलीभीत मार्ग समेत करीब एक दर्जन स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। रोड शो में 400 से अधिक चार पहिया और दोपहिया वाहन शामिल रहे। सैकड़ों समर्थक पार्टी के समर्थन में नारे लगाते हुए कैंप कार्यालय तक पहुंचे, जहां रोड शो का समापन हुआ।

इससे पहले आयोजित कुर्मी समाज की महापंचायत में स्थानीय नेतृत्व और समाज की एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। महापंचायत में मौजूद लोगों ने डॉ. रत्नेश गंगवार के नाम पर समर्थन जताते हुए उन्हें समाज की आवाज के रूप में आगे बढ़ाने की बात कही।

रोड शो के बाद पत्रकार वार्ता में डॉ. गंगवार ने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के विकास संबंधी दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी तस्वीर दावों से अलग है। जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सुविधाओं, रोजगार और बुनियादी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा कर रही है।

उन्होंने क्षेत्र में मिनी स्टेडियम, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोडवेज बस स्टैंड की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. गंगवार ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी हाईकमान उन्हें प्रत्याशी बनाएगा और वह क्षेत्र में पार्टी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे।

कार्यक्रम में रामप्रताप गंगवार, राम सिंह गंगवार, सुधा यादव, राम सिंह यादव, हाकिम सिंह यादव, बंटी शर्मा, बीडी प्रजापति, यासीन अंसारी, बलीउल्लाह, अकील अंसारी, गायत्री गंगवार, शैलेश शर्मा, अभिषेक गंगवार, राशिद अल्वी, जिवेन्द्र गंगवार, विवेक गंगवार, भगवत शरण, देवेंद्र कुमार, अकरम अंसारी, दानिश अल्वी, नन्हे चौधरी, अंकित वर्मा, उजाला बाबू और श्रीपाल निराला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे।

यमुना का जलस्तर बढ़ा तो सजेती थाना पुलिस क्षेत्र एवं ग्राम वासियो की सुरक्षा दृष्टि से हुई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पहुंची टीम

(जीएनएस)।

कानपुर शहर में लगातार हो रही बारिश और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट की साउथ जोन पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके के निर्देशन में एसीपी के नेतृत्व में सजेती थाना पुलिस ने नदी किनारे और जलभराव की आशंका वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया।*

पुलिस टीमों ने यमुना नदी के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से बातचीत कर उन्हें संभावित खतरे को लेकर सचेत किया। ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से नदी के करीब जाने, पानी में उतरने और जोखिम वाले स्थानों पर भीड़ लगाने से बचने की सलाह दी गई।*

✍पुलिस ने लोगों से अपील की कि बारिश और नदी के जलस्तर को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। जलभराव या नदी का पानी बढ़ने की स्थिति में तत्काल सुरक्षित स्थान की ओर जाने और पुलिस-प्रशासन के निदेर्शों का पालन करने को कहा गया।

✍सजेती पुलिस ने स्पष्ट किया कि जलस्तर और मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति में समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

मंडलायुक्त के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई, पिज्जा हट एवं डोमिनोज में मिलीं विभिन्न अनियमितताएं; संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिवस का नोटिस जारी

(जीएनएस)।

मंडलायुक्त के निदेर्शों के क्रम में खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिज्जा हट एवं डोमिनोज के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण में पृथक्करण की व्यवस्था से संबंधित कमियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की यूज-बाय डेट/डिस्कार्ड डेट के समुचित निस्तारण, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं में भी कमियां पाई गईं।

उक्त कमियों के दृष्टिगत संबंधित खाद्य कारोबारकताओं को 14 दिवस का नोटिस जारी कर कमियों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. पिज्जा हट, एस.पी. मार्ग, सिविल लाइंस

दिनांक 31 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पिज्जा हट, एस.पी. मार्ग, सिविल लाइंस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त बर्तनों के लिए अलग पहचान/व्यवस्था नहीं पाई गई तथा दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के भंडारण को भी अलग-अलग चिन्हित नहीं किया गया था। साथ ही खाद्य पदार्थों पर अंकित यूज-बाय डेट/डिस्कार्ड डेट का समय से समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त मुख्य रसोई में कर्मचारियों द्वारा हेड कवर, ग्लव्स एवं एप्रन का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। पिज्जा की पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री के खाद्य-ग्रेड होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तैयार पिज्जा को गर्म अवस्था में परोसने के लिए प्रयुक्त कॉर्क पैड गंदी अवस्था में पाया गया। प्रिपरेशन एवं क्लीनिंग क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था उचित नहीं थी तथा नालियां चोक पाई गईं। कर्मचारियों के अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, फूड लाइसेंस में अंकित जिम्मेदार व्यक्ति से संबंधित सूचना तथा फूड सेफ्टी चेकलिस्ट भी उपलब्ध/अद्यतन नहीं पाई गई।

2. पिज्जा हट, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइंस

दिनांक 31 अगस्त 2026 को ही पिज्जा हट, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइंस का भी निरीक्षण किया गया। यहां वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त बर्तनों का पृथक्करण चिन्हित नहीं था तथा डीप फ्रीजर में वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के अलग-अलग भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई।

इसके अतिरिक्त पिज्जा निर्माण में संलग्न कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे। परिसर के वाशिंग सिंक की जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं थी। पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम तथा क्लीनिंग कार्यक्रम की एसओपी/चेकलिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई।

3. डोमिनोज, एस.पी. मार्ग, सिविल लाइंस

दिनांक 01 सितंबर 2026 को एस.पी. मार्ग, सिविल लाइंस स्थित डोमिनोज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्ड चैंबर में वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के पृथक्करण की व्यवस्था चिन्हित नहीं पाई गई।

इसके अतिरिक्त पिज्जा निर्माण कार्य में संलग्न कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे तथा कुछ कर्मचारियों द्वारा पिज्जा तैयार करते समय हैंड ग्लव्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। मुख्य रसोई क्षेत्र में कर्मचारियों के लोडिंग बैग, हेलमेट आदि रखे पाए गए, जिन्हें अलग निर्धारित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए। पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम तथा क्लीनिंग कार्यक्रम की एसओपी/चेकलिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई।

साथ ही डिलीवरी बॉय अथवा किसी अनधिकृत व्यक्ति के मुख्य रसोई क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए पिछले द्वार से केवल अधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

4. कोरांव बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण

आज दिनांक 01 सितंबर 2026 को कोरांव बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। ट्रिमेंड गंज रोड, कोरांव स्थित दीपक स्वीट हाउस एवं कंचन स्वीट हाउस का निरीक्षण कर बर्फी एवं मिल्क केक के एक-एक विधिक नमूने संग्रहित किए गए।

इसके पश्चात मांडा रोड, कोरांव पहुंचने पर संबंधित दुकान बंद पाई गई। वहीं देवरा मोड़ स्थित शौर्य स्वीट हाउस, संचालक गोलू केसरी पुत्र मूलचंद केसरवानी, का निरीक्षण किया गया। प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया।

इसी क्रम में लेड़ियारी बाजार स्थित उमाशंकर केसरवानी की दुकान का भी निरीक्षण किया गया तथा बेसन के लड्डू का एक विधिक नमूना संग्रहित किया गया। संग्रहित नमूनों को नियमानुसार जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

5. डोमिनोज पिज्जा, लोकसेवा, जॉर्ज टाउन

दिनांक 31 अगस्त 2026 को लोकसेवा, जॉर्ज टाउन स्थित डोमिनोज पिज्जा का भी निरीक्षण किया गया। यहां वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त बर्तनों के लिए अलग पहचान की व्यवस्था नहीं थी तथा दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों के भंडारण को अलग-अलग इंगित नहीं किया गया था। साथ ही खाद्य पदार्थों पर अंकित यूज-बाय डेट/डिस्कार्ड डेट का समुचित निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त मुख्य रसोई में कर्मचारियों द्वारा हेड कवर, ग्लव्स एवं एप्रन का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। पिज्जा की पैकिंग में प्रयुक्त सामग्री के खाद्य-ग्रेड होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तैयार पिज्जा को गर्म अवस्था में परोसने के लिए प्रयुक्त कॉर्क पैड गंदी अवस्था में पाया गया। कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम, फूड लाइसेंस में अंकित जिम्मेदार व्यक्ति से संबंधित सूचना तथा अद्यतन फूड सेफ्टी चेकलिस्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त कमियों एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत संबंधित प्रतिष्ठानों को 14 दिवस के भीतर कमियों में सुधार कर आवश्यक अभिलेखों सहित अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में निदेर्शों का अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

तेज बारिश में सड़क किनारे गिरा सूखा शीशम, दबकर बुजुर्ग मजदूर की मौत; ग्रामीणों ने पेड़ हटाकर पहुंचाया अस्पताल

(जीएनएस)।

पीलीभीत,बरखेड़ा थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 60 वर्षीय मजदूर मुन्नालाल की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ा सूखा और जर्जर शीशम का पेड़ अचानक गिरा और मुन्नालाल उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ हटाकर उन्हें बाहर निकाला और तत्काल सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

हादसे का वक्त और जगह

बरखेड़ा थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव के पास बरखेड़ाझगजरौला मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 8 बजे यह घटना घटी। तेज बारिश और हवा के बीच

सड़क किनारे खड़ा शीशम का पेड़ अचानक गिर गया, जिससे रास्ते में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर आवागमन भी बाधित रहा।

मृतक का परिचय और घटनाक्रम

मुन्नालाल पुत्र रामचंद्र लाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, भोपतपुर गांव के रहने वाले थे और मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह सुबह बरखेड़ा से भोपतपुरझदौलतपुर पट्टी होते हुए गजरौला मार्ग की ओर गए थे; नदी के पुल के पास उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ीं और पैदल ही घर लौट रहे थे। लौटते समय तेज बारिश में वही सूखा पेड़ उनके ऊपर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

बचाव प्रयास और अस्पताल में घोषित मौत

हादसा देखकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद भारी पेड़ हटाकर मुन्नालाल को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत बरखेड़ा के सरकारी अस्पताल (सीएचसी) ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिवार में मातम; पत्नी और चार बेटे रोते रहे

मुन्नालाल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी इंद्रा देवी और चारों बेटों का रो-रोकर बुरा हाल रहा; मुन्नालाल मजदूरी करके ही घर की जिम्मेदारी संभालते थे।

सितंबर में समाधान नहीं तो अक्टूबर में होगा बड़ा आंदोलनः भाकियू भानु

लंबित समस्याओं को लेकर किसानों ने मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन, प्रशासन को दी चेतावनी

(जीएनएस)।

पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन भानु की जिला स्तरीय मासिक पंचायत मंगलवार को मंडी परिषद स्थित कृषक विश्राम गृह में जिला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी की अध्यक्षता में हुई। पंचायत में किसानों की पूर्व में उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई और मंडी सचिव पीलीभीत को पुनः मांग-पत्र सौंपा।

जिलाध्यक्ष भजनलाल क्रोधी ने

कहा कि जिले में आवारा पशुओं, मंडी समिति, बिजली-पानी, जलभराव और मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने यातायात पुलिस पर किसानों से चौराहों पर अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। साथ ही श्रम परिवर्तन अधिकारी कार्यालय में कथित अनियमितताओं तथा आरटीओ कार्यालय में दलालों के माध्यम से ही ड्राइविंग लाइसेंस बनने की शिकायत भी उठाई।

भाकियू ने प्रशासन को चेतावनी दी कि सितंबर में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अक्टूबर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने आंदोलन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होने की बात कही।

पंचायत में नंदकिशोर राठौर, अशोक राठौड़, बालमुकुंद प्रजापति, रघुवर सिंह प्रजापति, निसहर शाह, अयूब खान, सुखलाल गंगवार समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

₹52 लाख की धोखाधड़ी में वांछित ₹15,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

(जीएनएस)।

कमिश्नरेट कानपुर नगर की कल्याणपुर थाना पुलिस ने 15 हजार रुपये के इनामी वांछित अपराधी इन्द्रेश सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। अभियुक्त वीएसीएल (श्अउछ) इंडिया रियल एस्टेट कंपनी के जरिए 5 साल में पैसे दोगुने करने और जमीन दिलाने का झांसा देकर ₹52 लाख की ठगी करने के मामले में वांछित था।

पुलिस टीम ने सर्विलांस व सटीक सूचना के आधार पर अभियुक्त को सेक्टर-8 पानी की टंकी के पास से दबोचा। अभियुक्त के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं; पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।